GEO IAS
It's about quality

THE HINDU
INDIA'S NATIONAL NEWSPAPER SINCE 1878

Daily News Analysis

The Hindu Important News Articles & Editorial For UPSC CSE

Wednesday, 27 Nov , 2024

Edition: International

Table of Contents

Page 05 **Syllabus : GS2 : भारतीय राजनीति**	CJI ने 'अनिर्वाचित' न्यायपालिका के बारे में कटाक्षों की निंदा की
Page 07 **Syllabus : GS 3 : विज्ञान और प्रौद्योगिकी**	थुंबा लॉन्च के छह दशक बाद, कई निजी संस्थाएं उड़ान भरने की तैयारी में हैं
Page 10 **Syllabus : GS 2 : भारतीय राजनीति**	समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला
Page 11 **Syllabus : प्रारंभिक तथ्य**	स्वीकरण नीतियों के लिए सामी और अन्य अल्पसंख्यक समूहों से नॉर्वे की माफ़ी
समाचार में	पैन 2.0
Page 08 : संपादकीय विश्लेषण: **Syllabus : GS 2 : भारतीय राजनीति**	गणतंत्र से असमानों के गणराज्य की ओर

GEO IAS
It's about quality

Page 05 : GS2 : Indian Polity – Judiciary

भारत के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना ने लोकतंत्र में निष्पक्ष निर्णय लेने के लिए न्यायपालिका की स्वतंत्रता को महत्वपूर्ण बताया और "अनिर्वाचित" न्यायाधीशों की आलोचनाओं का जवाब दिया।

- उन्होंने लंबित मामलों, सार्वजनिक जांच और संवैधानिक कर्तव्यों के बीच संतुलन जैसी चुनौतियों पर प्रकाश डाला, साथ ही न्यायिक उत्पादकता में सुधार का भी प्रदर्शन किया।

CJI flays barbs about 'unelected' judiciary

Krishnadas Rajagopal
NEW DELHI

Chief Justice of India Sanjiv Khanna on Tuesday threw a counter-punch at critics who question the power wielded by "unelected" judges in an electoral democracy, indicating the alternative is even more frightening.

"But imagine a world where judges campaign for votes, solicit views and decisions from the public and make promises about future judgments...", Chief Justice Khanna addressed his audience, including Prime Minister Narendra Modi, at a Constitution Day function.

Appointment of judges, and not voting them to power, was a way to ensure

Sanjiv Khanna

their decisions were unbiased and free from "external pressures". Their conduct was guided solely by the Constitution and the law.

Chief Justice Khanna said judges walk the razor's edge. Their decisions make some happy while drawing criticism from others.

The CJI said some rate the constitutional courts of India among the most powerful in the world. Others felt the courts were straying from their constitutional duties by either failing to challenge the status quo or in resisting the transient popular mandate of the electorate.

'Duty towards public'

"For judges, perspectives and critique matter, because our foremost duty is towards the public, and secondly, being open and transparent is the biggest strength of the judiciary," he said.

The CJI said judges were certainly not above reproach. Constructive feedback would only make the judiciary more efficient, citizen- and public-centric and accountable.

"By opening ourselves to scrutiny, we can identify systemic inefficiencies and bottlenecks, and work towards eliminating them," Chief Justice Khanna said.

The Chief Justice said judicial independence was not a high wall, but a bridge. Each branch of government was not "a satellite in an independent orbit but rather a related actor which works in a degree of separateness".

He flagged pendency as a prime concern. He said the scale of cases flowing through courts was "staggering". The CJI pointed out that the district courts received 2.08 crore cases, the High Courts around 16.6 lakh and the Supreme Court 54,000.

Pending cases

"Therefore, it is not surprising that about 4.54 crore cases are pending in the district courts and 61.10 lakh cases are pending in the High Courts... But the case clearance rate in district courts – a key metric of judicial productivity – has risen steadily from 98.29% in 2022 to an impressive 101.74% in 2024. Last year alone, our district courts resolved over 20.14 lakh criminal and 8.09 lakh civil cases," he noted.

The Supreme Court, too, has enhanced its performance, with case clearance rate climbing from 95% to 97%, the CJI said.

लोकतंत्र में न्यायिक स्वतंत्रता

- भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) संजीव खन्ना ने चुनावी लोकतंत्र में न्यायपालिका की शक्ति के बारे में आलोचनाओं का जवाब दिया, जिसमें अभियानों के माध्यम से न्यायाधीशों के चुने जाने के खतरों पर जोर दिया गया।
- उन्होंने बताया कि नियुक्ति प्रणाली निष्पक्ष निर्णय लेने को सुनिश्चित करती है, बाहरी दबावों से मुक्त होती है, और संविधान और कानून द्वारा निर्देशित होती है।
- सीजेआई ने इस बात पर प्रकाश डाला कि न्यायाधीशों को जनता की अपेक्षाओं और आलोचना के बीच संतुलन बनाने की चुनौती का सामना करना पड़ता है, क्योंकि उनके निर्णयों पर अक्सर अलग-अलग प्रतिक्रियाएँ आती हैं।

चुनावी लोकतंत्र में न्यायपालिका की शक्ति पर बहस

- **चुनावी लोकतंत्र में न्यायपालिका की शक्ति के पक्ष में तर्क**
  - o जाँच और संतुलन: न्यायपालिका विधायी और कार्यकारी शाखाओं पर एक महत्वपूर्ण जाँच के रूप में कार्य करती है, शक्ति के दुरुपयोग को रोकती है और संविधान का पालन सुनिश्चित करती है।
  - o अधिकारों की सुरक्षा: न्यायपालिका नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करती है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा करती है और न्याय सुनिश्चित करती है।

- o कानूनों की व्याख्या: न्यायपालिका कानूनों की व्याख्या करती है और उनके सुसंगत अनुप्रयोग को सुनिश्चित करती है, कानूनी निश्चितता को बढ़ावा देती है और मनमाने निर्णयों को रोकती है।
- o स्वतंत्र समीक्षा: न्यायपालिका सरकार के कार्यों की स्वतंत्र समीक्षा करती है, उन्हें जवाबदेह ठहराती है और पारदर्शिता सुनिश्चित करती है।

चुनावी लोकतंत्र में न्यायपालिका की शक्ति के विरुद्ध तर्क

- न्यायिक सक्रियता: नीतिगत मामलों में अत्यधिक न्यायिक हस्तक्षेप लोकतांत्रिक प्रक्रिया को कमजोर कर सकता है और न्यायपालिका के राजनीतिकरण को बढ़ावा दे सकता है।
- सीमित विशेषज्ञता: न्यायाधीशों के पास जटिल नीतिगत मुद्दों पर सूचित निर्णय लेने के लिए आवश्यक विशेषज्ञता की कमी हो सकती है।
- निर्णय लेने में देरी: न्यायिक प्रक्रियाएँ लंबी हो सकती हैं, जिससे नीति कार्यान्वयन में देरी हो सकती है और विकास में बाधा आ सकती है।
- पूर्वाग्रह की संभावना: न्यायाधीश, किसी भी अन्य मनुष्य की तरह, पूर्वाग्रहों और पूर्वाग्रहों के अधीन हो सकते हैं, जो संभावित रूप से उनके निर्णयों को प्रभावित कर सकते हैं।

भारतीय न्यायपालिका पर वैश्विक और राष्ट्रीय दृष्टिकोण

- भारत की संवैधानिक अदालतों को वैश्विक स्तर पर सबसे शक्तिशाली माना जाता है।
- हालाँकि, इस बात की चिंता है कि अदालतें या तो महत्वपूर्ण मुद्दों को संबोधित नहीं कर रही हैं या क्षणिक लोकप्रिय जनादेश का विरोध कर रही हैं।

न्यायपालिका का कर्तव्य और जवाबदेही

- सीजेआई ने इस बात पर जोर दिया कि न्यायाधीशों का सबसे बड़ा कर्तव्य जनता के प्रति है, और खुला और पारदर्शी होना न्यायपालिका की ताकत को बढ़ाता है।
- रचनात्मक आलोचना न्यायपालिका को बेहतर बनाने में मदद करती है, जिससे यह अधिक कुशल, नागरिक-केंद्रित और जवाबदेह बनती है।
- उन्होंने कहा कि न्यायिक स्वतंत्रता सरकार की विभिन्न शाखाओं के बीच सहयोग को बढ़ावा देने वाला एक पुल है, न कि अलगाव की ऊंची दीवार।

न्यायालयों में लंबित मामलों की संख्या

- विभिन्न न्यायालयों में मामलों की चौंका देने वाली संख्या के साथ लंबित मामले एक गंभीर चिंता का विषय बने हुए हैं:
- जिला न्यायालय: 2.08 करोड़ मामले दर्ज किए गए, जिनमें से 4.54 करोड़ लंबित हैं।
- उच्च न्यायालय: लगभग 16.6 लाख मामले दर्ज किए गए, जिनमें से 61.10 लाख लंबित हैं।
- सर्वोच्च न्यायालय: 54,000 मामले लंबित हैं।

इसके बावजूद, उत्पादकता में उल्लेखनीय सुधार हुआ है:

- जिला न्यायालयों की केस निपटान दर 2022 में 98.29% से बढ़कर 2024 में 101.74% हो गई, जिससे अकेले 2023 में 28.23 लाख से अधिक मामलों का समाधान हुआ।
- सुप्रीम कोर्ट की केस निपटान दर 95% से बढ़कर 97% हो गई।

चुनौतियाँ और आगे का रास्ता

- न्यायपालिका प्रणालीगत अक्षमताओं और बाधाओं का सामना करती है, जिन पर ध्यान देने की आवश्यकता है।
- जांच के लिए खुली रहकर, न्यायपालिका दक्षता सुनिश्चित करने के लिए चुनौतियों की पहचान कर सकती है और उनका समाधान कर सकती है।
- न्यायिक स्वतंत्रता जवाबदेही को बढ़ावा देती है, जबकि संविधान को बनाए रखने और सार्वजनिक हितों को प्रभावी ढंग से पूरा करने के लिए सरकार की विभिन्न शाखाओं के बीच सहयोग को सक्षम बनाती है।

UPSC Mains PYQ : 2023

प्रश्न: संवैधानिक रूप से गारंटीकृत न्यायिक स्वतंत्रता लोकतंत्र की एक पूर्व शर्त है। टिप्पणी करें। (150 Words /10 marks)

GEO IAS
It's about quality

यह लेख भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम में महत्वपूर्ण मील के पत्थर पर प्रकाश डालता है, जो 1963 में पहले रॉकेट प्रक्षेपण के 61 साल पूरे होने का जश्न मनाता है।

- इसमें हाल की प्रगति, जैसे कि GSAT-N2 का प्रक्षेपण और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में निजी क्षेत्र का योगदान भी शामिल है।

Six decades since Thumba launch, slew of private entities prepare for flight

The Departments of Space and of Biotechnology have signed agreements to conduct biological experiments on the forthcoming Bharatiya Antariksh Station; while researchers will be able to conduct experiments on other missions as well, the agreement pertains to experiments onboard the station

Pradeep Mohandas

November 21 was 61 years since the birth of the Indian space programme. On this date in 1963, scientists launched a Nike-Apache sounding rocket from Thumba in Kerala. These rockets helped the Indian Space Research Organisation (ISRO) master the solid propellant technology powering India's launch vehicles today. Around the same time as this anniversary, India launched its first satellite onboard a SpaceX rocket even as multiple Indian private sector entities geared up for launches of their own.

Launches of merit

NewSpace India, Ltd. launched the 4,700-kg GSAT-N2/GSAT-20 satellite onboard a SpaceX Falcon 9 rocket from Florida. N2 wasn't launched onboard an Indian launch vehicle because its weight exceeded the payload capacity of the country's most powerful rocket, the LVM-3, which can place satellites weighing up to four tonnes in the geostationary transfer orbit (GTO). INSAT-1D was the last such satellite launched from Florida, in 1990.

GSAT-N2 is a Ka-band high throughput communication satellite built by ISRO to enhance broadband services in underserved areas, including the northeast, Andaman & Nicobar Islands, and Lakshadweep. It will also support services like in-flight internet connectivity and the Smart Cities Mission.

The satellite was placed in a GTO with a perigee of 250 km, an apogee of 59,730 km, and at a 27.5°inclination. From here, the satellite will use its thrusters to move to a geostationary orbit at 63° E longitude over the next few days.

Next, ISRO is preparing to launch its PSLV-C59 mission bearing the European Proba-3 mission. The Polar Satellite Launch Vehicle (PSLV) will fly in its extended length configuration (XL), which was last used to launch Aditya-L1 in September 2023.

The twin Proba spacecraft to study the Sun arrived in Chennai on November 6 and will be integrated with the launch vehicle. Liftoff is currently scheduled for 4 p.m. IST on December 4.

India's astronaut-designate Shubhanshu Shukla, who is set to fly to the International Space Station in 2025, is undergoing training at the European Space Agency's European Astronaut Centre. This part of the training is to familiarise astronauts-to-be with the European modules of the space station.

From the private sector

Four Indian private companies are preparing to launch their payloads/satellites into orbit.

A Nike-Apache two-stage rocket on its launcher at Thumba, Kerala. THE HINDU ARCHIVES

Pixxel, which is Indian-American, unveiled 'Fireflies', its six hyperspectral satellites expected to be launched early next year. Each satellite weighs around 50 kg, has a native 5 m spatial resolution, and scans 40-km swaths for data in more than 150 spectral bands. These satellites constitute the first batch in what is eventually expected to become a constellation of 24 satellites. These satellites are capable of providing data that can help detect crop diseases, water-stressed areas, real-time deforestation, and ocean pollution early.

Second, GalaxEye Space is flying its "It's NOT a Satellite, It's Just a Tech Demo" on board the PSLV's Orbital Experimental Module (POEM) platform. This is when the final stage of a PSLV finishes deploying its payload and enters earth orbit, becoming an orbital platform where onboard instruments can run experiments. The Tech Demo will test subsystems of a synthetic aperture radar (SAR).

PierSight Space will also fly a mission on a PSLV POEM called 'Varuna', which will demonstrate a deployable reflectarray antenna and test SAR and aeronautical information service avionics in orbit.

HEX20 will fly its 'Nila' satellite onboard SpaceX's Transporter 13 mission in February 2025. 'Nila' is a 5-kg cubesat that can host different payloads and provide data-processing services. A ground station will be built in Thiruvananthapuram, Kerala, to control and receive data from the satellite.

India recently launched its first satellite onboard a SpaceX rocket even as multiple Indian private sector entities geared up for launches of their own

Catalyx Space's SR-0 satellite launched onboard the third developmental flight of the Small Satellite Launch Vehicle mission re-entered the earth's atmosphere on November 3. The company announced the satellite had achieved all its objectives in its three-month lifespan.

AAKA Space Studio launched India's first Space Analog Mission in Leh, Ladakh, in collaboration with the ISRO Human Spaceflight Centre, IIT-Bombay, and the University of Ladakh. The site was chosen for its similarity to surfaces on the moon and Mars.

One person from AAKA Space Studio will stay in the habitat in Leh for 21 days to test habitat sustainability, life-support systems, and the human experience of isolation.

SatSure is working with the Ministry of Electronics and Information Technology for "automated image feature extraction models for building footprints, roof type, roads, and water bodies among other classes for more than two lakh villages". This is the Indian government's largest programme to map rural property. Drones under the government's 'Svamvita' programme will capture images of 3-5 cm resolution and SatSure will use its machine-learning tools developed for satellite data to extract and classify the relevant features.

Space science updates

India celebrated its full membership of the Square Kilometre Array Observatory (SKAO), an international effort to build the world's most advanced radio telescope in Australia and South Africa. India will contribute cash as well as advanced electronics and engineering for telescope components in exchange for scientific data collected by the telescope.

The first scientific result from the Visible Emission Line Coronagraph onboard the Aditya-L1 spacecraft was published in the *Astrophysical Journal Letters*.

A team led by researchers at the Indian Institute of Astrophysics, Bengaluru, used data from the coronagraph to accurately predict the time of a coronal mass ejection on July 16. Coronal mass ejections affect satellites in orbit, electricity grids on the ground, and radio communications when they blow past the planet.

Finally, the Departments of Space and of Biotechnology have signed agreements to conduct biological experiments on the forthcoming Bharatiya Antariksh Station. While researchers will be able to conduct experiments on other missions (including the uncrewed Gaganyaan flights), the agreement pertains to experiments onboard the Indian space station.

(Pradeep Mohandas is a technical writer and space enthusiast in Pune. pradeep.mohandas@gmail.com)

THE GIST

- NewSpace India Ltd. launched the 4,700-kg GSAT-N2/GSAT-20 satellite onboard a SpaceX Falcon 9 rocket from Florida
- Pixxel, which is Indian-American, unveiled 'Fireflies', its six hyperspectral satellites expected to be launched early next year
- PierSight Space will also fly a mission on a PSLV POEM called 'Varuna', which will demonstrate a deployable reflectarray antenna
- HEX20 will fly its 'Nila' satellite onboard SpaceX's Transporter 13 mission in February 2025

भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के 61 वर्ष पूरे होने का जश्न

- भारत ने अपने अंतरिक्ष कार्यक्रम के 61 वर्ष पूरे होने का जश्न मनाया, जिसमें 1963 में केरल के थुंबा से नाइक-अपाचे रॉकेट का प्रक्षेपण याद किया गया।
- इस प्रक्षेपण ने ठोस प्रणोदक प्रौद्योगिकी में इसरो की महारत की नींव रखी।

योग्यता के प्रक्षेपण

- न्यूस्पेस इंडिया लिमिटेड ने भारत के LVM-3 रॉकेट की वजन सीमाओं के कारण स्पेसएक्स फाल्कन 9 रॉकेट पर 4,700 किलोग्राम का GSAT-N2 उपग्रह लॉन्च किया।
- GSAT-N2, एक Ka-बैंड संचार उपग्रह है, जिसका उद्देश्य वंचित क्षेत्रों में ब्रॉडबैंड को बढ़ाना और इन-फ़्लाइट इंटरनेट और स्मार्ट सिटी मिशन जैसी सेवाओं का समर्थन करना है।
- 4 दिसंबर को निर्धारित PSLV-C59 मिशन, सूर्य का अध्ययन करने के लिए यूरोपीय प्रोबा-3 मिशन को ले जाएगा।

निजी क्षेत्र का योगदान

- पिक्सेल: फसल रोगों का पता लगाने और प्रदूषण की निगरानी करने में सक्षम छह हाइपरस्पेक्ट्रल उपग्रहों को लॉन्च करने की तैयारी।
- गैलेक्सआई स्पेस और पियरसाइट स्पेस: PSLV के POEM प्लेटफ़ॉर्म का उपयोग करके SAR तकनीक और रिफ्लेक्टरेरे एंटेना का परीक्षण।
- HEX20: 2025 में स्पेसएक्स के ट्रांसपोर्टर 13 मिशन पर अपना 'नीला' उपग्रह लॉन्च करना।
- AAKA स्पेस स्टूडियो: चंद्रमा और मंगल मिशनों के लिए आवास स्थिरता का परीक्षण करने के लिए लेह में एक स्पेस एनालॉग मिशन का संचालन करना।

वैज्ञानिक उपलब्धियाँ

- भारत दुनिया के सबसे बड़े रेडियो टेलीस्कोप में योगदान देने के लिए स्क्वायर किलोमीटर एरे ऑब्ज़र्वेटरी में शामिल हुआ।
- आदित्य-L1 के शोधकर्ताओं ने उपग्रह और संचार सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण कोरोनल मास इजेक्शन पर निष्कर्ष प्रकाशित किए।
- अंतरिक्ष और जैव प्रौद्योगिकी विभागों के बीच समझौते आगामी भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन पर जैविक प्रयोगों को सक्षम करेंगे।

UPSC Mains Practice Question

प्रश्न: भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के विकास और भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र में निजी क्षेत्र के योगदान पर चर्चा करें। वैश्विक सहयोग में भारत की अंतरिक्ष विज्ञान पहलों की भूमिका का विश्लेषण करें, विशेष रूप से स्क्वायर किलोमीटर एरे ऑब्ज़र्वेटरी में इसकी भागीदारी का। (150 words/10m)

GEO IAS
It's about quality

Page 10 : GS 2 : Indian Polity – Judiciary

लेख में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 'समाजवादी' और 'धर्मनिरपेक्ष' शब्दों को शामिल करने के बारे में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर चर्चा की गई है।

- इसमें ऐतिहासिक संदर्भ, कानूनी घटनाक्रम और इन शब्दों के खिलाफ चुनौतियों को हाल ही में खारिज किए जाने की रूपरेखा दी गई है।
- न्यायालय ने पुष्टि की कि ये शब्द संविधान की मूल संरचना का अभिन्न अंग हैं।

SC ruling on socialism, secularism

What was the original Preamble and how has it evolved? What has been the court's stand earlier and how has it changed? What was the current case about? What bearing will it have on the society?

EXPLAINER

Rangarajan R

The story so far:

A Division Bench of the Supreme Court led by the Chief Justice of India dismissed pleas challenging the inclusion of the words 'socialist' and 'secular' in the Preamble to our Constitution.

What is the history of Preamble?

The original Preamble adopted on November 26, 1949, declared India a sovereign, democratic, republic. Our Constituent Assembly consciously avoided the word 'socialist' as they felt that declaring the economic ideal of a country in its Constitution's preamble was not appropriate. People should decide what suits them according to time and age.

Likewise, Indian secularism is different from western secularism. In the latter, the state and religion are strictly separated and the government does not interfere in religious affairs. However, in India, the state enjoys the power to regulate the economic, financial, political and secular aspects associated with religious practice. It can also provide for social welfare and reform in religious practices. Further, various provisions of the Constitution that include right to practise any religion, non-discrimination on the basis of religion in any affairs of the state embodied the 'secular' values of our Constitution. Hence, in the Constituent Assembly, the amendment to introduce the word 'secular' in the Preamble was not accepted.

In Berubari case (1960), the Supreme Court opined that the Preamble is not a part of the Constitution and thus not a source of any substantive power. Subsequently, in Kesavananda Bharati case (1973), the Supreme Court reversed its earlier opinion and said that the Preamble is part of the Constitution and that it should be read and interpreted in the light of the vision envisioned in the Preamble. It also held that the Preamble is subject to the amending power of Parliament as any other provision of the Constitution. The 42nd Constitutional Amendment in 1976 inserted the words 'Socialist', 'Secular' and 'Integrity' in the Preamble.

Guiding book: Indian National Congress (INC) party workers carry a model of the Indian Constitution during in rally on the occasion of Constitution Day celebrations in Kolkata on Tuesday. AFP

What was the current case?

The current case was filed by former Rajya Sabha MP Subramanian Swamy, advocate Ashwini Upadhyay and others. Mr. Upadhyay and others had opposed the insertion of the words 'socialist' and 'secular' in the Preamble. They argued that these were included during the Emergency and forced the people to follow specific ideologies. They felt that since the date of adoption by the Constituent Assembly was mentioned in the Preamble, no additional words can be inserted later by Parliament. Mr. Swamy was of the view that subsequent amendments to the Constitution including the 44th Amendment in 1978 during Janata Party rule after emergency had supported and retained these two words. Nevertheless, he was of the view that these words should appear in a separate paragraph below the original Preamble.

What did the court rule?

The court dismissed the pleas and held that 'socialism' and 'secularism' are integral to the basic structure of the Constitution. It observed that the Constitution is a 'living document' subject to the amendment power of Parliament. This amending power extends to the Preamble as well and the date of adoption mentioned in it does not restrict such power. The court opined that 'socialism' in the Indian context primarily means a welfare state that provides equality of opportunity and does not prevent the private sector from thriving. Similarly, over time India has developed its own interpretation of 'secularism'. The state neither supports any religion nor penalises the profession and practice of any faith. In essence, the concept of secularism represents one of the facets of right to equality.

Why is it important?

The initial years after Independence fostered 'democratic socialism' characterised by centralised planning and many industries being established by the state. The period of 1960s and 70s saw nationalisation of banks and insurance, higher tax rates and various regulations. The economy, though declared as mixed economy where public and private enterprises would co-exist, displayed the characteristics of classical socialism with license controls and regulations. Starting from 1991, our economy has evolved from such socialistic pattern to a market-oriented model. The ensuing growth has uplifted vast majority of people from abject poverty in the last three decades. However, there is also growing inequality that needs to be addressed. As the court observed, our socialism continues to address the needs of the poor through schemes such as MGNREGA, subsidised food grains, direct benefit transfers for women and farmers etc. Hence, it is imperative that such socialism continues to guide the actions of the state for the welfare of the needy while private enterprise flourishes resulting in increased employment and strong economic growth. The spirit of our 'unity in diversity' should be equally preserved by upholding the values of secularism.

Rangarajan R is a former IAS officer and author of 'Polity Simplified'. Views expressed are personal.

THE GIST

- The original Preamble adopted on November 26, 1949, declared India a sovereign, democratic, republic. Our Constituent Assembly consciously avoided the word 'socialist' as they felt that declaring the economic ideal of a country in its Constitution's preamble was not appropriate.
- Indian secularism is different from western secularism. In the latter, the state and religion are strictly separated and the government does not interfere in religious affairs. However, in India, the state enjoys the power to regulate the economic, financial, political and secular aspects associated with religious practice.
- The current case was filed by those opposed to the insertion of the words 'socialist' and 'secular' in the Preamble. They argued that these were included during the Emergency and forced the people to follow specific ideologies.

प्रस्तावना का इतिहास

- 26 नवंबर, 1949 को अपनाई गई मूल प्रस्तावना ने भारत को एक संप्रभु, लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित किया।
- 'समाजवादी' शब्द को जानबूझकर प्रस्तावना से बाहर रखा गया था क्योंकि संविधान सभा को लगा कि आर्थिक दिशा संविधान में तय होने के बजाय समय के साथ विकसित होनी चाहिए।

- भारतीय धर्मनिरपेक्षता पश्चिमी मॉडल से अलग है। भारत में, राज्य कुछ क्षेत्रों में धार्मिक प्रथाओं को नियंत्रित करता है, धार्मिक स्वतंत्रता का सम्मान करते हुए सुधारों और कल्याण को बढ़ावा देता है।
- 'धर्मनिरपेक्ष' को शामिल करने के संशोधन को संविधान सभा की चर्चाओं के दौरान स्वीकार नहीं किया गया था।

कानूनी घटनाक्रम

- बेरुबारी केस (1960): सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है और इसमें कोई ठोस शक्ति नहीं है।
- केशवानंद भारती केस (1973): कोर्ट ने इस फैसले को पलटते हुए कहा कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है और इसकी व्याख्या इसके मूल दृष्टिकोण के अनुरूप की जानी चाहिए। संविधान के अन्य प्रावधानों की तरह ही प्रस्तावना में भी संशोधन किया जा सकता है।
- 42वाँ संविधान संशोधन (1976): इस संशोधन ने प्रस्तावना में 'समाजवादी', 'धर्मनिरपेक्ष' और 'अखंडता' शब्द शामिल किए।

वर्तमान मामला

- सुब्रमण्यम स्वामी, अश्विनी उपाध्याय और अन्य द्वारा दायर मामले में प्रस्तावना में 'समाजवादी' और 'धर्मनिरपेक्ष' शब्दों को शामिल किए जाने को चुनौती दी गई।
- याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि आपातकाल के दौरान जोड़े गए ये शब्द विशिष्ट विचारधाराओं को थोपते हैं और प्रस्तावना के मूल पाठ में बदलाव नहीं करना चाहिए।
- हालांकि, याचिकाकर्ताओं ने 44वें संशोधन (1978) जैसे बाद के संशोधनों के माध्यम से जोड़े गए इन शब्दों का विरोध नहीं किया।

न्यायालय का निर्णय

- सर्वोच्च न्यायालय ने याचिकाओं को खारिज करते हुए कहा कि 'समाजवादी' और 'धर्मनिरपेक्ष' संविधान के मूल ढांचे का अभिन्न अंग हैं।
- न्यायालय ने पुष्टि की कि संविधान एक जीवित दस्तावेज है और इसमें संशोधन किए जा सकते हैं, गोद लेने की तिथि इस शक्ति को प्रतिबंधित नहीं करती है।
- न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि भारत में समाजवाद का अर्थ है अवसर की समानता को बढ़ावा देने वाला कल्याणकारी राज्य, जबकि धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है सभी धर्मों का सम्मान करने वाला एक तटस्थ राज्य।

फैसले का महत्व

- भारत का समाजवाद निजी उद्यम का समर्थन करते हुए मनरेगा और प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण जैसी कल्याणकारी नीतियों का मार्गदर्शन करना जारी रखता है।
- भारत की विविधता में एकता को बनाए रखने के लिए धर्मनिरपेक्षता आवश्यक है।

'धर्मनिरपेक्ष' और 'समाजवादी' शब्दों की व्याख्या

- 'धर्मनिरपेक्ष' की सर्वोच्च न्यायालय की व्याख्या सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि भारत में धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है कि राज्य न तो किसी धर्म का समर्थन करता है और न ही उसके साथ भेदभाव करता है।
- यह सभी धर्मों के लिए समान सम्मान सुनिश्चित करता है और नागरिकों को अपने धर्म का स्वतंत्र रूप से पालन करने के अधिकार की गारंटी देता है।
- यह व्याख्या संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 16 पर आधारित है, जो धर्म के आधार पर भेदभाव को प्रतिबंधित करते हैं।
- ये प्रावधान कानून के तहत समान सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं और सार्वजनिक रोजगार में समान अवसरों की गारंटी देते हैं, जो संविधान के धर्मनिरपेक्ष लोकाचार को मजबूत करते हैं।
- 'समाजवादी' की सर्वोच्च न्यायालय की व्याख्या सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि भारत के संदर्भ में 'समाजवादी' का अर्थ है कल्याणकारी राज्य होने के लिए राज्य की प्रतिबद्धता, अवसर की समानता और सामाजिक-आर्थिक न्याय सुनिश्चित करना।
- यह किसी विशिष्ट आर्थिक नीति को निर्धारित नहीं करता, चाहे वह वामपंथी हो या दक्षिणपंथी।
- यह शब्द संविधान के सामाजिक कल्याण को बढ़ावा देने और असमानता को दूर करने के लक्ष्य को दर्शाता है।
- भारत एक मिश्रित अर्थव्यवस्था मॉडल को अपनाता है, जहाँ निजी क्षेत्र और सरकार दोनों ही आर्थिक विकास को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

UPSC Mains Practice Question

प्रश्न: भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 'समाजवादी' और 'धर्मनिरपेक्ष' शब्दों के महत्व की जाँच करें। उनके समावेश पर सर्वोच्च न्यायालय के हालिया फैसले और संविधान की व्याख्या के लिए इसके निहितार्थों पर चर्चा करें। (150 Words /10 marks)

GEO IAS
It's about quality

Page 11 : Prelims Facts

नॉर्वे की संसद ने सामी, केन और फॉरेस्ट फिन लोगों से एक शताब्दी से अधिक समय से चली आ रही भेदभावपूर्ण समावेशन नीतियों के लिए बिना शर्त माफी मांगी।

Norway's apology to Sami and other minority groups for assimilation policies

A century-long process of Norwegianisation of indigenous peoples and migrant groups commenced in the 1850s. These policies finally came to an end in the 1960s, with laws formally repealed or replaced in 1963. Yet, discrimination has continued the groups have been adversely affected

EXPLAINER

Sruthi Darbhamulla

The story so far:-

Last week, Norway's Parliament, the Storting, issued an unreserved apology for its assimilation policies towards Sami, Kven and Forest Finn peoples. It also laid out a series of resolutions to address the continuing discrimination faced by these communities, *The New York Times* reported.

A century-long process of Norwegianisation of indigenous peoples and migrant groups commenced in the 1850s and did not officially end till the 1960s. It saw the suppression of indigenous languages and traditional culture. Further, Sami children were separated from their parents and sent to boarding schools all across the Sapmi – 'the land of the Sami' which corresponds with present-day northern Russia, Finland, Norway and Sweden.

Who are the Samis, Kvens and Forest Finns?

Norway has designated certain groups with 'long-standing attachment to the country' as national minorities, including the Kvens/Norwegian Finns, Jews, Forest Finns, Roma and the Romani people. The Sami, meanwhile, are an Indigenous people spread across northern Europe, including Finland, Sweden, Norway and Russia. This region has been called Lapland; however the terms Lapps/Laplanders are considered derogatory by some Sami. Only about 1,00,000 Sami remain. The largest Sami population is concentrated in Norway – considered the heart of Sapmi – in areas such as Finnmark county.

Inhabiting this chilly terrain for centuries, the Sami have developed their own culture and unique way of life. Many are reindeer herders, and the Norwegian government has designated reindeer herding as an activity exclusive to the Sami, issuing herding licenses based on ancestral lands.

Sami languages are any of three languages (sometimes considered dialects of one overarching language) belonging to the Finno-Ugric group of the Uralic language family – North Sami, East Sami and South Sami.

Both Kvens and Forest Finns are much smaller groups (than the Sami) which migrated to present-day Norway around 500 years ago.

Kvens are the descendants of migrants from the Torne River Valley, part of present-day Sweden and Finland, who historically practised slash and burn farming, fishing and blacksmithing. The Kven language, a Finnic language closely related to Meänkieli and Finnish, was recognised as an independent language in Norway in April 2005. Forest Finns, meanwhile, are descendants of immigrants from eastern Finland who settled in Sweden in the 1500s, before making their way to Norway in the early 1600s.

What were the Norwegianisation policies?

Indigenous peoples and minority groups historically faced discrimination from Scandinavian governments, and laws in the second half of the nineteenth century gave this historical prejudice a more solid form in Norway.

Many Sumis are reindeer herders, and the Norwegian government has designated reindeer herding as an activity exclusive to the Sami.AP

Norway engaged in a century-long process of "Norwegiansation" and assimilation, which intensified after the nation gained independence in 1905.

Policies to integrate and assimilate these groups by suppressing their native language and culture emerged. These policies used education and religion as a tool to erase local language and culture. Traditional practices such as 'yoiking,' a traditional call of the Samis, were forbidden during this time. Young Sami children were taken away from their parents and forced to live in foster homes and state-run boarding schools in the 1900s. The government demarcated some regions for "suitable populations," where these groups were not allowed to settle. Groups also lost access to grazing land and fishing grounds.

Native cultural beliefs were suppressed by Christian mission churches belonging to the Evangelical Lutheran and Catholic denominations. The Sami were forced to give up their earlier shamanistic rituals.

Social discrimination persisted under the guise of scientific research. Members from these communities were made to undergo anthropological tests by scientists, and their burial grounds were exhumed to study the ethnic characteristics of their predecessors.

These Norwegianisation policies finally came to an end in the 1960s, with laws formally repealed or replaced in 1963.

What is the Truth and Reconciliation Committee?

Measures at the community and government level were taken up to address the past oppression. Today, the Sami have a university as well as schools teaching the Sami language, and a (mostly symbolic) independently elected Sami Parliament established in 1989, with which the Norwegian parliament has a working relationship. The Education Act of 1969 gave Sami students the right to compulsory and upper-secondary education in their own language, and policies have also sought to integrate the language in school curricula.

Community efforts too have persisted to preserve the unique identity of these groups. For example, Young Forest Finns works to revive the group's culture and also has a museum under development.

The Truth and Reconciliation Commission was launched in 2018 to investigate the historical injustice and suggest measures for inclusion and revitalisation versus earlier policies of Norwegianisation and assimilation.

The Committee released a 700-page report on June 1, 2023. The current apology and a set of 17 resolutions to address prejudice against these groups stem from this report, which took 35 hours to read aloud in parliament, and was broadcast nationally. Recommendations in the report included the establishment of a centre for reconciliation work, preservation of minority and indigenous languages and language training.

Other Nordic nations too have launched similar commissions, including the Truth Commission for the Sami People in Sweden and the Truth and Reconciliation Commission Concerning the Sami People in Finland. Both are expected to present their reports sometime next year.

What is the current apology?

The unreserved apology was tendered last week to the Sami, Kvens and Forest Finns by the Norwegian parliament following on the heels of last year's Truth and Reconciliation Commission report. The move was approved by the Parliament and the apology read out loud on November 11.

All lawmakers except one group – a bloc from the right-wing Progress Party – voted for the resolution. This cited possible conflict among communities as a reason for voting against it. In a debate held in May, the party's leader, Bard Hoksrud, said it was " fundamentally wrong to give special privileges to some groups at the expense of others," adding that they believed that "history should remain history."

In a written response to a question from a journalist, Conservative party member Svein Haberg said, "The assimilation policy that was historically pursued continues to be both the root of personal hardship for the individuals and groups that were subject to this policy, and a source of conflict today."

Silje Karine Muotka, a Sami leader, called it "a day with many emotions," in a written statement. "Going forward, we expect an active policy of reconciliation.....The decision from today ensures long-term follow-up, and it has both financial and legal repercussions. But unfortunately, no settlement is made with ongoing injustice and conflicts over land and water," she wrote.

In 1977, King Harald V apologised to the Sami people, and Sami People's Day has been celebrated since 1993 on February 6 (the first Sami National Congress was held on February 6, 1917 in Trondheim, Norway). However, this is the first instance of a public apology to the Kvens and Forest Finns.

What are the continuing challenges?

Even after the formal repealing of the laws, prejudice in the nation has continued. The report by the Truth and Reconciliation Commission found that members of these groups have less access to health care in Norway, a country with a robust social security net.

The Sami have had a longstanding dispute with the Norwegian government over their way of life and land use, although some laws exist over the Samis' right to grazing land. A 2007 law sought to limit the size of reindeer herds – ostensibly to prevent overgrazing, a move opposed by some Sami herders.

Indigenous and minority languages, too, remain critically endangered. Bullying, hate speech and harassment has persisted, as have negative stereotypes.

As reported by *The New York Times*, a 2021 survey was conducted as part of an Arctic University of Norway project which studied the efficacy of the Truth and Reconciliation Commission. According to the results of this survey, 60% of Norway residents said they thought most people knew little to nothing about how the assimilation policies affected the Sami. That figure rose to 88% when it came to how the practices affected Forest Finns and Kvens.

The project was led by Eva Josefsen, a political scientist at the Arctic University who is Sami herself. She highlighted that the lack of transparency about land rights was a sticking point, saying that there was a "general implementation gap between legal rights and what is actually delivered."

- यह माफ़ी सत्य और सुलह आयोग के निष्कर्षों के बाद आई है, जिसने इन समुदायों के सामने आने वाली चुनौतियों पर प्रकाश डाला है।

खबरों में अल्पसंख्यक समूह:

- सामी - फिनलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और रूस सहित उत्तरी यूरोप में फैले स्वदेशी लोग, नॉर्वे में सबसे बड़ी आबादी के साथ। वे अपनी हिरन पालन संस्कृति और अनूठी भाषा के लिए जाने जाते हैं।
- क्वेन्स - नॉर्वे में बसने वाले टॉर्ने नदी घाटी (वर्तमान स्वीडन और फिनलैंड) के प्रवासियों के वंशज। वे ऐतिहासिक रूप से स्लैश-एंड-बर्न खेती, मछली पकड़ने और लोहार का काम करते थे।
- फ़ॉरेस्ट फ़िन - पूर्वी फ़िनलैंड के प्रवासियों के वंशज जो स्वीडन में बस गए और फिर 1600 के दशक में नॉर्वे चले गए। उनकी एक अलग सांस्कृतिक पहचान और भाषा है।
- यहूदी, रोमा और रोमानी लोग - इन समूहों को नॉर्वे में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक भी माना जाता है, जिनका देश से लंबे समय से संबंध है।

वे खबरों में क्यों हैं?

- ऐतिहासिक अन्याय: इन समूहों को एक सदी से भी ज़्यादा समय तक जबरन आत्मसात करने की नीतियों, भाषा दमन और सांस्कृतिक विलोपन का सामना करना पड़ा।
- जारी भेदभाव: उन्हें लगातार पूर्वाग्रह, स्वास्थ्य सेवा तक सीमित पहुँच और अपनी भाषाओं और परंपराओं को संरक्षित करने में चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है।
- सुलह के प्रयास: सत्य और सुलह आयोग और नॉर्वे की संसद द्वारा हाल ही में माफ़ी माँगने से अतीत और चल रहे भेदभाव को दूर करने के लिए मान्यता, क्षतिपूर्ति और सक्रिय प्रयासों की आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया है।

GEO IAS
It's about quality

In News : PAN 2.0

हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत की कर पहचान प्रणाली को आधुनिक बनाने के लिए PAN 2.0 परियोजना को मंजूरी दी।

- इसका उद्देश्य स्थायी खाता संख्या (PAN) को QR कोड, एक कागज रहित ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया और PAN, TAN और TIN को मिलाकर व्यवसायों के लिए एक एकीकृत पहचानकर्ता जैसी सुविधाओं के साथ उन्नत करना है।

समाचार का विश्लेषण

- PAN 2.0 का परिचय: आयकर विभाग द्वारा जारी 10 अंकों का अल्फ़ान्यूमेरिक पहचानकर्ता, स्थायी खाता संख्या (PAN), PAN 2.0 परियोजना के तहत उन्नत किया जा रहा है।
- प्रमुख परिवर्तनों में शामिल हैं: नए और मौजूदा दोनों PAN कार्ड पर एक QR कोड का एकीकरण।
- PAN कार्ड जारी करने और उन्हें उन्नत करने के लिए एक पूरी तरह से ऑनलाइन, कागज रहित आवेदन प्रक्रिया।
- TAN (कर कटौती और संग्रह खाता संख्या) और TIN (करदाता पहचान संख्या) जैसी अन्य पहचान संख्याओं के साथ विलय करके PAN सामान्य व्यवसाय पहचानकर्ता बन जाएगा।

सरकारी स्वीकृति और उद्देश्य

- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 25 नवंबर, 2024 को ₹1,435 करोड़ के बजट के साथ PAN 2.0 परियोजना को मंजूरी दी।
- इसका लक्ष्य डेटा की स्थिरता और विश्वसनीयता सुनिश्चित करके व्यक्तियों और व्यवसायों के लिए PAN को "सत्य का एकमात्र स्रोत" बनाना है।

व्यक्तियों और व्यवसायों के लिए लाभ

- **व्यक्ति:**
  - o लगभग 78 करोड़ PAN धारक अपने कार्ड को अपग्रेड कर सकते हैं, जिसमें वही PAN नंबर रहेगा लेकिन QR कोड जैसी उन्नत सुविधाएँ होंगी।
  - o सभी मौजूदा उपयोगकर्ताओं को अपग्रेड निःशुल्क प्रदान किया जाएगा।
- **व्यवसाय:**
  - o PAN विभिन्न कर रिटर्न और चालान दाखिल करने के लिए एक सहज, एकीकृत प्रणाली के रूप में काम करेगा, जिससे कई पहचानकर्ताओं की आवश्यकता कम हो जाएगी।
  - o यह व्यवसायों के लिए अनुपालन को सरल बनाएगा, एकल व्यवसाय पहचानकर्ता की लंबे समय से चली आ रही माँगों को संबोधित करेगा।

PAN 2.0 की मुख्य विशेषताएँ

- **QR कोड एकीकरण:**
  - o सभी PAN कार्ड (पुराने और नए) में एक QR कोड एकीकृत किया जाएगा, जिससे आयकर विभाग के साथ वित्तीय लेनदेन को जोड़ने की क्षमता बढ़ेगी।
  - o यह सुविधा, जिसे पहली बार 2017 में पेश किया गया था, PAN 2.0 में सुधार की जाएगी।
- **PAN डेटा वॉल्ट सिस्टम:**
  - o बैंक और बीमा कंपनियों जैसे संगठन जो PAN डेटा का उपयोग करते हैं, उन्हें इस जानकारी को अनिवार्य डेटा वॉल्ट सिस्टम में सुरक्षित रूप से संग्रहीत करना होगा।
  - o इस उपाय का उद्देश्य डेटा सुरक्षा और साइबर सुरक्षा को बढ़ाना है।
- **एकीकृत ऑनलाइन पोर्टल:**
  - o एक नया, आधुनिक पोर्टल पुराने सॉफ़्टवेयर (वर्तमान में 15-20 वर्ष पुराना) की जगह लेगा।
  - o पोर्टल एक पेपरलेस प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित करेगा और इसमें शिकायत निवारण के लिए सुविधाएँ शामिल होंगी, जिससे यह अधिक उपयोगकर्ता के अनुकूल बन जाएगा।
- **प्रणालियों का एकीकरण:**

o कर अनुपालन प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने और सेवा वितरण में सुधार करने के लिए PAN/TAN/TIN प्रणालियों को विलय किया जाएगा।

प्रौद्योगिकी-संचालित परिवर्तन

- PAN 2.0 परियोजना का उद्देश्य मुख्य और गैर-मुख्य गतिविधियों को एकीकृत करके करदाता पंजीकरण सेवाओं का आधुनिकीकरण करना है।
- परियोजना सेवा वितरण को बढ़ाने और करदाताओं के लिए बेहतर पहुँच प्रदान करने के लिए नई तकनीक भी पेश करेगी।

वित्तीय लेन-देन पर प्रभाव

- सुधारित क्यूआर कोड एकीकरण वित्तीय लेन-देन और आयकर विभाग के बीच संबंध को मजबूत करेगा, जिससे पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ेगी।
- पैन 2.0 से वित्तीय लेन-देन में त्रुटियों और धोखाधड़ी में उल्लेखनीय कमी आने की उम्मीद है।

मौजूदा पैन और टैन कार्य

- **पैन:**

  o पैन एक अद्वितीय पहचानकर्ता के रूप में कार्य करता है जो किसी व्यक्ति या व्यवसाय के वित्तीय लेन-देन (जैसे, कर भुगतान, आयकर रिटर्न, टीडीएस/टीसीएस क्रेडिट) को आयकर विभाग से जोड़ता है।

  o यह आयकर रिटर्न दाखिल करने के लिए अनिवार्य है और धारक के जीवन भर अपरिवर्तित रहता है।

- **टैन:**

  o टैन एक 10-अंकीय अल्फ़ान्यूमेरिक संख्या है जो स्रोत पर कर काटने या एकत्र करने के लिए जिम्मेदार संस्थाओं द्वारा आवश्यक है।

  o इसे टीडीएस/टीसीएस रिटर्न, चालान और प्रमाणपत्रों में उद्धृत किया जाना चाहिए।

- **निष्कर्ष**
- पैन 2.0 परियोजना भारत के कर बुनियादी ढांचे में सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। आधुनिक तकनीक को एकीकृत करके, डेटा सुरक्षा सुनिश्चित करके और अनुपालन को सरल बनाकर, सरकार का लक्ष्य व्यक्तियों और व्यवसायों के लिए PAN की उपयोगिता और प्रभावशीलता को बढ़ाना है। यह पहल वित्तीय प्रणालियों को अधिक कुशल, पारदर्शी और सुरक्षित बनाने का वादा करती है।.

UPSC Mains PYQ : 2022

प्रश्न: कल्याणकारी योजनाओं के अलावा, भारत को समाज के गरीब और वंचित वर्गों की सेवा के लिए मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के प्रबंधन की भी आवश्यकता है। चर्चा करें। (250 words/15m)

GEO IAS
It's about quality

GEO IAS
It's about quality

THE HINDU
INDIA'S NATIONAL NEWSPAPER SINCE 1878

Daily News Analysis

Page : 08 Editorial Analysis

From a republic to a republic of unequals

Venkata-narayanan Sethuraman

Associate Professor and Head of the Department of International Studies, Political Science and History at Christ University, Bengaluru

Constitution day on November 26, 2024 marked 75 years of the adoption of the Constitution and constitutional governance in independent India. The Constituent Assembly debates show the intellectual engagement of leaders from a spectrum of ideologies, right wing to left wing, in building a single political identity that was accommodative of the interests and rights of multiple cultural groups.

The Constitution-makers accepted the liberal framework, but wanted the state to play a positive role in intervening and reducing inequality due to poor social indicators at the time of Independence. With liberalism, as a political ideology, there was an insistence that there should be freedom for citizens to carry out activities without any state interference. There was the belief that only in a free environment could human potentialities, be they intellectual, moral and physical, be realised. Thus, liberty became the core value of liberalism.

The Indian Constitution makers agreed to create a liberal political state in India. But considering the social and economic inequalities, they felt that a complete withdrawal of the state would perpetuate the existing inequalities and worsen it further. So, it was that the state should be given a positive role to intervene and create conditions for everyone to participate equally in the development process. Thus, affirmative action and reservation policies to treat unequals in an unequal manner to achieve the constitutional vision of equality have become an important aspect of the Indian Constitution.

An egalitarian outlook

Its vision of equality aims to create an egalitarian society to minimise economic inequalities among the people. Reflecting John Rawls' egalitarian liberalism, including the three important principles of equal basic liberties, equal opportunities and difference, the Constitution aims to create an egalitarian society. The fundamental rights in Part III and the Directive Principles of State Policy (DPSP) in Part IV of the Constitution reflect all the above three principles of egalitarian liberalism. Thus egalitarian liberalism aims to reduce inequality and not create an absolute equal society. Article 38(2) of DPSP insists that the state shall strive to minimise the inequalities of income and eliminate inequalities in status, facilities and opportunities. The constitutional ideological framework lays emphasis on reducing inequalities and creating an egalitarian society based on equal opportunities and facilities through state intervention. Further, Article 39(c) emphasises that the economic system ought not to result in a concentration of wealth and means of production to the common detriment.

The Supreme Court of India has reiterated this principle in many of its judgments till the end of the 1990s. In *D.S. Nakara & Others vs Union Of India* (1982), the Court said that the basic framework of socialism in the Constitution is to provide a decent standard of life to the working people and social security from cradle to grave, reiterating the role of the welfare state in India. In *Air India Statutory Corporation vs United Labour Union & Ors* (1996), the Court said that the ideological aspects of the Indian Constitution found in the Preamble, Fundamental Rights and DPSP aim to establish an egalitarian social order, protecting social and economic justice and the dignity of individual by providing equality of status and opportunities.

In *Samatha vs State of Andhra Pradesh & Ors.* (1997), the Court interpreted that the meaning of the word "socialism" in the Constitution is to reduce inequalities in income and provide equal opportunities and facilities to create an egalitarian social order. Justice V.R. Krishna Iyer's interpretation of Article 39(b) of the DPSP, in *State Of Karnataka And Anr Etc vs Shri Ranganatha Reddy & Anr. Etc*, that public and private resources fall within the ambit of community resources, was in line with the constitutional ideology of creating an egalitarian society by strengthening the state's power of redistribution of resources for common good towards reducing inequality.

But recently, the Court overturned this interpretation without locating it within Article 39(c), which empowers the state to intervene and regulate the economic system to prevent the concentration of wealth in the hands of a few towards creating an egalitarian society.

> The neoliberal ideological order shadows the constitutional vision of creating an egalitarian social order in India

Economic reforms and inequality

After the adoption of neoliberal economic reforms in India, the constitutional ideology took a back seat and the idea of a welfare state as envisaged in the Constitution has withdrawn its commitments towards creating an egalitarian society. Lucas Chancel and Thomas Piketty from the Paris School of Economics have documented the rising inequality in India in their work, "Indian Income Inequality, 1922-2015: From British Raj to Billionaire Raj?" (2019).

Their research shows that the top 1% of earners had a share of less than 21% of total income in the 1930s. But after Independence, due to welfare state intervention, based on constitutional ideology, this gap reduced where the top 1% earners had a share of 6% of the total income in the 1980s.

After the implementation of neoliberal reforms in the 1990s, there were major structural changes that happened in the Indian economy, which prioritised private capital investment and a slow withdrawal of the welfare interventionist state. The state took the positive role of creating and strengthening markets rather than working towards creating an egalitarian society, as envisaged in the Constitution. As a consequence of this, the top 1% income has reached 22% of the total income pushing back to an inequality situation worse than that in the pre-Independence period. They reiterated this inequality status in their recent research in 2024 emphasising that the top 1% of income and wealth shares have reached 22.6% and 40.1% by 2022-23, which is considered very high.

The "State of Inequality in India Report" (2022), prepared by the Institute for Competitiveness (commissioned by the Economic Advisory Council to the Prime Minister), highlighted the Periodic Labour Force Survey 2019-20, which recorded that average monthly wages of ₹25,000 (₹3 lakh an annum) is being earned by the top 10% and the remaining 90% earn less than ₹.25,000 a month. This shows extreme inequality and how the majority are being pushed into poverty, violating constitutional ideology.

An overlap with social inequality

Further, the report titled "Towards Tax Justice and Wealth redistribution in India" (2024 by the World Inequality Lab at the Paris School of Economics), has brought in evidence to show how economic inequality and social inequality overlap in India. By 2022-23, 90% of the billionaire wealth was held by the upper castes in India. Scheduled Tribes are not present in billionaire wealth. Other Backward Classes (OBC) have a mere 10% presence and Scheduled Castes have a 2.6% representation in billionaire wealth. The report further emphasises that between 2014 and 2022, the OBC share has reduced from 20% to 10% and upper caste share has increased from 80% to 90% in billionaire wealth. The upper castes are the only group which owns wealth more than its proportion of population, reiterating how social capital and economic advantages are overlapping in India. Further, Oxfam International highlights the rise in the number of billionaires from nine in the year 2000 to 119 in 2023. It further compares income inequality and shows that it will take 941 years for a minimum wage earner to earn what a top corporate executive earns a year in India.

The constitutional vision of creating an egalitarian social order by minimising income inequality and eliminating social inequality is under threat from the neoliberal ideological order. Violating the constitutional ideology, inequality levels are widening, strengthening wealth concentration among the few. Further, social inequality overlaps with economic inequality to give the upper castes a greater advantage in contemporary India. Constitution Day has passed, but there is an opportunity for us to critically evaluate our political and economic practices within the constitutional framework, to assess our achievements and failures, reiterating Babasaheb's words that social and economic inequality will put political democracy in peril.

GS Paper 02 : भारतीय राजनीति

PYQ: (UPSC CSE (M) GS-1 2020): कोविड-19 महामारी ने भारत में वर्ग असमानता और गरीबी को बढ़ा दिया है। टिप्पणी करें। (150 words/10m)

UPSC Mains Practice Question: जांच करें कि नवउदारवादी आर्थिक सुधारों ने भारत में सामाजिक-आर्थिक असमानताओं को कम करने के संवैधानिक दृष्टिकोण को कैसे प्रभावित किया है। आर्थिक और सामाजिक असमानताओं के बीच ओवरलैप के निहितार्थों पर चर्चा करें। (150 Words /10 marks)

संदर्भ:

- भारतीय संविधान की समतावादी दृष्टि राज्य के हस्तक्षेप और सकारात्मक कार्रवाई के माध्यम से सामाजिक-आर्थिक असमानताओं को संबोधित करने की कोशिश करती है।
- हालाँकि, नवउदारवादी सुधारों ने आय और धन असमानताओं को बढ़ाया है, संसाधनों को कुछ लोगों के बीच केंद्रित किया है, और संवैधानिक आदर्शों को कमजोर किया है।
- आर्थिक और सामाजिक असमानता का यह ओवरलैप संविधान निर्माताओं द्वारा परिकल्पित लोकतांत्रिक ताने-बाने को खतरे में डालता है।

संविधान का बौद्धिक आधार

- 75 साल पहले अपनाया गया संविधान, विभिन्न विचारधाराओं वाले नेताओं के बीच बहस को दर्शाता है, जो सांस्कृतिक और सामाजिक विविधता को समायोजित करने वाली राजनीतिक पहचान बनाने पर केंद्रित है।
- व्यक्तिगत स्वतंत्रता को महत्व देने वाले उदारवाद को अपनाते हुए, संविधान निर्माताओं ने सामाजिक और आर्थिक असमानताओं को कम करने के लिए राज्य के हस्तक्षेप पर जोर दिया।

सकारात्मक कार्रवाई और समतावादी दृष्टिकोण

- संविधान का उद्देश्य सकारात्मक कार्रवाई और आरक्षण नीतियों के माध्यम से असमानता को संबोधित करके एक समतावादी समाज बनाना है।
- जॉन रॉल्स के समतावादी उदारवाद के सिद्धांतों से प्रेरित, संविधान में शामिल हैं:
- समान बुनियादी स्वतंत्रता और अवसर।
- पूर्ण समानता को अनिवार्य किए बिना असमानता को कम करने के लिए अंतर सिद्धांत।
- अनुच्छेद 38(2) और अनुच्छेद 39(सी) के तहत राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत (डीपीएसपी) आय असमानताओं को कम करने और धन के संकेन्द्रण को रोकने पर ध्यान केंद्रित करते हैं।

समतावाद के लिए न्यायिक समर्थन

- **ऐतिहासिक निर्णयों ने संविधान के समतावादी आदर्शों को बरकरार रखा है:**

o डी.एस. नाकारा और अन्य बनाम भारत संघ (1982): एक सभ्य जीवन और सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने में कल्याणकारी राज्य की भूमिका पर जोर दिया।
o समथा बनाम आंध्र प्रदेश राज्य (1997): समाजवाद की व्याख्या आय असमानताओं को कम करने और समान अवसर प्रदान करने के रूप में की गई।
o न्यायमूर्ति वी.आर. कृष्ण अय्यर ने कर्नाटक राज्य बनाम रंगनाथ रेड्डी (1977) में सामुदायिक संसाधन वितरण को असमानता को कम करने से जोड़ा।

नवउदारवादी सुधारों का प्रभाव

- 1990 के बाद के आर्थिक सुधारों ने निजी पूंजी को प्राथमिकता दी और कल्याणकारी हस्तक्षेपों को कम किया।
- असमानता में वृद्धि हुई है, 2022-23 तक शीर्ष 1% के पास आय का 22.6% और संपत्ति का 40.1% हिस्सा होगा, जो स्वतंत्रता-पूर्व स्तर को पार कर जाएगा।
- भारत में असमानता की स्थिति रिपोर्ट (2022) से पता चला है कि शीर्ष 10% लोग ₹25,000/माह से अधिक कमाते हैं, जबकि बाकी लोग इससे कम कमाते हैं, जो आय में भारी असमानता को दर्शाता है।

सामाजिक और आzक असमानता का अंतर्संबंध

- विश्व असमानता प्रयोगशाला (2024) ने अतिव्यापी असमानताओं पर प्रकाश डाला:
- अरबपतियों की 90% संपत्ति उच्च जातियों के पास है।
- अनुसूचित जनजातियों का प्रतिनिधित्व नहीं है, जबकि अनुसूचित जाति और ओबीसी के पास क्रमशः 2.6% और 10% है।
- ओबीसी की संपत्ति का हिस्सा 20% से घटकर 10% (2014-2022) हो गया, जबकि उच्च जाति का हिस्सा 80% से बढ़कर 90% हो गया।
- ऑक्सफैम इंटरनेशनल ने अरबपतियों की संख्या में 9 (2000) से 119 (2023) की वृद्धि और आय में अत्यधिक असमानताओं पर ध्यान दिया।

निष्कर्ष: संवैधानिक आदर्शों पर पुनर्विचार

- असमानता को कम करने और समतावादी समाज बनाने की संवैधानिक दृष्टि नवउदारवादी ढांचे के विपरीत है।
- बढ़ती असमानता राजनीतिक लोकतंत्र को खतरे में डालती है, जो बाबासाहेब अंबेडकर की इस चेतावनी की पुष्टि करती है कि असमानता लोकतांत्रिक मूल्यों को खतरे में डालती है।
- संविधान दिवस नीतियों का पुनर्मूल्यांकन करने और उन्हें सामाजिक और आर्थिक न्याय के आदर्शों के साथ संरेखित करने की याद दिलाता है।

GEO IAS
It's about quality